नईदुनिया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से द्रास के लिए मोटरसाइकिल अभियान को दिखाई हरी झंडी

कारगिल विजय दिवस से पहले 'शौर्य विजय यात्रा' का शुभारंभ

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस से पहले मंगलवार को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक तक आयोजित 13 दिवसीय 'शौर्य विजय यात्रा' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान में सेना के सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ उनके परिवारों सहित 28 मोटरसाइकिल सवार भाग ले रहे हैं। यह दल 1,900 किलोमीटर की यात्रा कर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध स्मारक पहुंचेगा।

इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों ने लगभग 20 हजार फुट की ऊंचाई और शून्य से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान जैसी कठिन परिस्थितियों में अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने दुश्मन के कब्जे से प्रत्येक चोटी और बंकर को मुक्त कर तिरंगे का गौरव बढ़ाया तथा देश की सुरक्षा के प्रति अपने अटूट संकल्प का परिचय दिया।

राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार मेजर संजय कुमार सहित सभी वीर सैनिकों के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका साहस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।

यात्रा के दौरान प्रतिभागी चंडीमंदिर, रेजांग ला और लेह सहित विभिन्न युद्ध स्मारकों पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

साथ ही शहीद सैनिकों की वीर नारियों से मिलकर उनका सम्मान भी करेंगे। मोटरसाइकिल सवार राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पवित्र मिट्टी से भरा एक कलश भी अपने साथ ले जा रहे हैं, जिसे कारगिल युद्ध स्मारक पर अर्पित किया जाएगा।

कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि, सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह यात्रा विशेष रूप से युवाओं में देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा की भावना को और मजबूत करेगी।

होर्मुज़ पर अब हमारा नियंत्रणः ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- क्षेत्र की स्थिति पर अमेरिका की पकड़, ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर होने का भी किया दावा

वाशिंगटन, एजेंसीः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर अब अमेरिका का नियंत्रण है। एक समाचार माध्यम को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की स्थिति पर अमेरिका की पकड़ बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ईरान कठिनाइयां उत्पन्न करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन नियंत्रण अमेरिका के पास है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब होर्मुज़ जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद तनाव बढ़ा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि हाल के अमेरिकी सैन्य अभियानों से ईरान की सैन्य क्षमता को गंभीर क्षति पहुंची है। उनके अनुसार ईरान के रडार तंत्र, गोला-बारूद, प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपण प्रणाली, मानव रहित विमान तथा अन्य सैन्य संसाधनों को नष्ट कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि अमेरिकी सेंट्रल कमान ने मंगलवार से ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी फिर लागू करने की घोषणा की है। उनके अनुसार यह नाकाबंदी उन सभी जहाजों पर लागू होगी, जो ईरान के साथ व्यापार करेंगे, चाहे वे किसी भी देश के ध्वज के तहत संचालित हो रहे हों। उन्होंने कहा कि इससे पहले लागू नाकाबंदी प्रभावी रही थी और अब इसे पुनः लागू किया जा रहा है।

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान की नौसेना, वायुसेना, रडार प्रणाली, विमान भेदी व्यवस्था तथा हथियार निर्माण क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि ईरान के पास अभी भी कुछ सैन्य क्षमता शेष है, लेकिन उनका कहना था कि वर्तमान स्थिति चार महीने पहले की तुलना में पूरी तरह बदल चुकी है और ईरान की सैन्य शक्ति पहले की अपेक्षा काफी कमजोर हो गई है।

होर्मुज़ में स्वतंत्र नौवहन होः भारत

विदेश मंत्रालय ने कहा, सुरक्षित समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः भारत ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन का समर्थन करते हुए इसे वैश्विक ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और उसका मानना है कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सुरक्षित तथा निर्बाध समुद्री आवागमन सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मार्ग दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज़ से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर 20 प्रतिशत सुरक्षा शुल्क लगाने की घोषणा की है।

सऊदी अरब-हूती तनाव बढ़ा युद्धविराम पर संकट के बादल

वाशिंगटन/रियाद/सना, एजेंसीः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यमन के हूती विद्रोहियों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के लिए सऊदी अरब को समर्थन दिए जाने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। सना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सऊदी हमले तथा उसके जवाब में हूती विद्रोहियों के प्रक्षेपास्त्र और मानव रहित विमान हमलों के बाद वर्ष 2022 से लागू अनौपचारिक युद्धविराम पर संकट गहरा गया है।

सूत्रों के अनुसार सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने हाल में ट्रंप से बातचीत कर हूतियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए समर्थन मांगा था, जिसके बाद अमेरिका ने सहमति दी। इसके बाद दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच भी कई दौर की वार्ताएं हुईं।

तनाव की शुरुआत उस समय हुई जब ईरान का एक विमान हूती नियंत्रित सना पहुंचा। लौटते समय सऊदी समर्थित यमन सरकार ने सना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के धावन मार्ग पर हमला किया, जिसके कारण विमान को होदेदाह की ओर मोड़ना पड़ा। यमन सरकार ने आरोप लगाया कि विमान में हथियार, प्रक्षेपास्त्रों के पुर्जे तथा सैन्य विशेषज्ञ मौजूद थे।

हमले के जवाब में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के अबहा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की दिशा में प्रक्षेपास्त्र और मानव रहित विमान दागे। हूती पक्ष ने चेतावनी दी कि यदि सना हवाई अड्डे पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो सऊदी हवाई क्षेत्र का उपयोग करने वाली अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं भी निशाने पर आ सकती हैं। हालांकि सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने सभी प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने का दावा किया है।

इस बीच यमन के कई प्रांतों में सना हवाई अड्डे पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन हुए। ईरान ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और यमन की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह संघर्ष और बढ़ा तो पहले से अमेरिका-ईरान तनाव से प्रभावित पश्चिम एशिया में व्यापक क्षेत्रीय टकराव का खतरा और गहरा सकता है।

बैंकॉक अग्निकांड में लापरवाही के संकेत

बंद आपातकालीन निकास और ज्वलनशील सजावट से बढ़ी जनहानि, मृतकों की संख्या 30 पहुंची

बैंकॉक, एजेंसीः थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी भीषण आग की प्रारंभिक जांच में गंभीर लापरवाही के संकेत मिले हैं। अधिकारियों के अनुसार, आपातकालीन निकास द्वार बंद थे और परिसर में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सजावटी सामग्री का उपयोग किया गया था। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है, जबकि 70 से अधिक लोग घायल हैं। इनमें 24 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस महानिदेशक कित्तिरात फानफेट ने बताया कि मंच के पास लगी आग ज्वलनशील सजावट के कारण तेजी से फैल गई। राहत दलों को अधिकांश शव शौचालयों में मिले, जहां लोग आग से बचने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाहर नहीं निकल सके।

प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण वातानुकूलन यंत्र में विद्युत शॉर्ट सर्किट माना गया है।

जांच में यह भी सामने आया कि मुख्य प्रवेश द्वारों के सामने सामान रखा था और आपातकालीन निकास के स्पष्ट संकेत नहीं थे। विशेषज्ञों के अनुसार, मंच और छत पर लगी ज्वलनशील सामग्री ने आग को तेजी से फैलाया, जबकि कई लोगों की मृत्यु जलने के बजाय जहरीला धुआं सांस में जाने से हुई होने की आशंका है।

दक्षिण चीन सागर पर भारत ने दोहराया अपना स्पष्ट रुख

समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और निर्बाध नौवहन पर अंतरराष्ट्रीय नियमों के पालन पर जोर

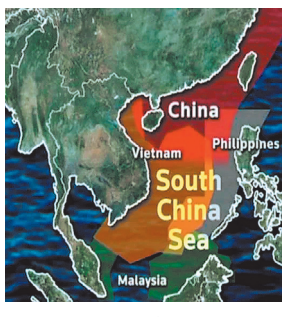

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः भारत ने दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख दोहराते हुए कहा है कि वह इस क्षेत्र में नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता, निर्बाध व्यापार तथा समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में कहा कि भारत का मानना है कि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के प्रावधानों और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत की नीति पहले से स्पष्ट है।

भारत नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्र के वैध उपयोग तथा निर्बाध व्यापार को बनाए रखने के महत्व पर बल देता है। साथ ही समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप किया जाना चाहिए। रणधीर जायसवाल ने कहा कि वर्ष 2016 में मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय इस विषय में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और संबंधित पक्षों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का आधार बना हुआ है।

उल्लेखनीय है कि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत गठित न्यायाधिकरण के 12 जुलाई 2016 के निर्णय की दसवीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत ने यह रुख दोहराया है। इसी निर्णय के आधार पर अमेरिका, ब्रिटेन, जापान तथा अनेक अन्य देशों ने भी दक्षिण चीन सागर में समुद्री दावों को लेकर अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया है। साथ ही क्षेत्र में स्थिरता, निर्बाध व्यापार और नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता दोहराई गई है।

ईरान का दावा, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया जवाबी हमला

बहरीन स्थित सैन्य अड्डों, रडार प्रणालियों और सैन्य परिसंपत्तियों को निशाना बनाने का दावा

तेहरान, एजेंसीः ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों, रडार प्रणालियों और अन्य सैन्य परिसंपत्तियों को निशाना बनाया है। संगठन के अनुसार, अभियान के दूसरे चरण में मिसाइलों और मानव रहित विमानों से हथियार भंडार, उपग्रह संचार केंद्र तथा सैनिकों के आवासीय परिसर पर हमला किया गया। संगठन ने यह

भी दावा किया कि अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े से जुड़े रडार और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को नष्ट कर दिया गया तथा ईंधन भंडार में आग लग गई। इसके अलावा होर्मुज़ जलडमरूमध्य में समुद्री नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दो विशाल तेलवाहक जहाजों को भी निशाना बनाने का दावा किया गया। संगठन ने कहा कि ईरान अपने समुद्री अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

उम्मीदवारी *विकासशील देशों की आवाज मजबूत करने और वैश्विक शांति को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता...*

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पेश की अपनी दावेदारी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 2028-29 के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करते हुए सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध विश्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के चुनाव अभियान का औपचारिक शुभारंभ करते हुए कहा कि विकासशील देशों की आवाज को सशक्त बनाना और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दों में उनकी चिंताओं को उचित स्थान दिलाना भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण संवाद, सहयोग और मतभेदों को दूर करने पर आधारित रहेगा। उन्होंने सुधार आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधित्वपूर्ण और प्रभावी बनाया जाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि भारत भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शांति स्थापना व्यवस्था को अधिक सक्षम, प्रौद्योगिकी समर्थ और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में कार्य करेगा। साथ ही महिला शांति सैनिकों की भूमिका को भी निरंतर प्रोत्साहन दिया जाएगा।

जयशंकर ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत समावेशी, सुरक्षित और मानव-केंद्रित दृष्टिकोण का समर्थन करेगा तथा इसके दुरुपयोग से उत्पन्न खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप स्वतंत्र और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था, सुरक्षित समुद्री व्यापार तथा समुद्री डकैती के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई पर भी जोर दिया।

विदेश मंत्री ने आतंकवाद के वित्तपोषण पर रोक लगाने और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध साक्ष्य आधारित तथा पारदर्शी प्रतिबंध व्यवस्था की आवश्यकता दोहराते हुए सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने का आग्रह किया।